भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4306 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशनों के रूप में उन्नत करना

4306. श्री अजय भट्ट:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संपूर्ण देश में विद्यमान रेल स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में और विशेषकर उत्तराखंड और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्मार्ट स्टेशनों के रूप में उन्नयन करने हेतु चिह्नित रेल स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ग) उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधि का वर्षवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त पुनर्विकास कार्यों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्मार्ट स्टेशनों के रूप में पहले से ही उन्नत या विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों की वर्षवार/राज्यवार संख्या कितनी है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। अब तक इस योजना के तहत देश भर में 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें

उत्तराखंड राज्य के 11 स्टेशन शामिल हैं । उत्तराखंड राज्य के पहचाने गए स्टेशनों की सूची नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	राज्य	संख्या	स्टेशनों के नाम
1	उत्तराखंड	11	देहरादून, हरिद्वार जं., हर्रावाला, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं जं., रामनगर, रूड़की, टनकपुर

इन 11 स्टेशनों में से 9 स्टेशनों पर विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। चिन्हित स्टेशनों पर कार्य अच्छी गति से शुरू हो चुका है। इनमें से कुछ स्टेशनों पर प्रगति इस प्रकार है:

लालकुआं स्टेशन पर स्टेशन आर्किटेक्चर में सुधार, प्लेटफार्म नंबर 4 को ऊपर उठाना और उसकी सतह में सुधार करना, दो व चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग, प्लेटफार्म की सतह को फिर से बनाना और वाटर बूथ बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। प्रतीक्षालय का नवीनीकरण, परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्रवेश/निकास द्वार, शौचालय ब्लॉक, प्लेटफार्म शेल्टरों को पुन: स्थापित करना, ऊपरी सड़क पुल का निर्माण आदि कार्य शुरू हो चुके हैं।

रामनगर स्टेशन पर शौचालय ब्लॉक, पीआरएस बिल्डिंग का विस्तार, वाटर बूथ और पार्किंग क्षेत्र में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र और प्रवेश द्वार प्रांगण के सुधार का कार्य शुरू हो चुका है।

किच्छा स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ऊपर उठाने और उसकी सतह में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। मौजूदा स्टेशन भवन के नवीनीकरण, यूटीएस के साथ नए स्टेशन भवन का निर्माण, प्रवेश/निकास द्वार, प्रतीक्षालय में सुधार, शौचालय ब्लॉक और प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य शुरू हो चुका है।

काशीपुर जंक्शन स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ऊंचाई बढ़ाने, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन में सुधार, लिफ्टों की व्यवस्था, शौचालय

ब्लॉक और प्लेटफार्म शेल्टर को पुन: स्थापित करने तथा प्रवेश द्वार प्रांगण का कार्य शुरू हो चुका है।

इस योजना में प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें मास्टर प्लान तैयार करना और उन्हें चरणों में लागू करना शामिल है, ताकि स्टेशनों पर सुविधाएं जैसे कि स्टेशन तक पहुँच में सुधार, परिभ्रमण क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, भूनिर्माण आदि सुविधाओं में सुधार हो सके।

इस योजना में भवन में सुधार, स्टेशन को शहर के दोनों ओर एकीकृत करना, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान, चरणबद्ध और व्यवहार्यता और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर का निर्माण आदि की परिकल्पना की गई है।

उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत एवं जारी प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता, धन की उपलब्धता आदि के अनुसार किए जाते हैं।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार, न कि राज्य-वार या स्टेशन-वार रखा जाता है। स्टेशनों के विकास और यात्री सुविधाओं के प्रावधान को आम तौर पर योजना शीर्ष - 53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत वित्तपोषित किया जाता है। उत्तराखंड के लिए दो क्षेत्रीय रेलवे अर्थात उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 से फरवरी 2025 तक) के दौरान योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए इन रेलवे जोनों पर आवंटित कुल धनराशि और व्यय क्रमशः ₹5405.12 करोड़ और ₹4293.07 करोड़ है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है, जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल है और इसके लिए अग्नि मंजूरी, विरासत, पेड़ों की कटाई, हवाई अड्डे की मंजूरी आदि जैसी विभिन्न वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। उपयोगिताओं का स्थानांतरण, (पानी/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, बिजली/सिग्नल केबल आदि शामिल हैं) का उल्लंघन, अतिक्रमण, यात्रियों की आवाजाही में बाधा डाले बिना रेलगाड़ियों का संचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के करीब किए गए कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड से संबंधित चुनौतियों के कारण भी प्रगति प्रभावित होती है तथा ये कारक कार्य पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती ।

*****